दृष्टि
The Vision

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

अगस्त (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **5**

- बाल सेवा योजना (Bal Seva Yojana) 5
- झाँसी स्टेशन के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव 5
- UPEIDA-SIDM के बीच रक्षा उद्योग मंच के लिये समझौता ज्ञापन 6
- उज्ज्वला योजना 2.0 (Ujjwala Yojana 2.0) 6
- 'काकोरी ट्रेन कांड'अब 'काकोरी ट्रेन एक्शन' 6
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान 7
- परिवहन विभाग द्वारा संभावित लाभार्थियों के लिये पंजीकरण शुरू 7
- हेमवती नंदन बहुगुणा (Hemvati Nandan Bahuguna) 8
- मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया 8
- राष्ट्रपति वीरता पदक (President's Gallantry Medal) 8
- 'जन आशीर्वाद यात्रा' 9
- एटीएस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र 9
- 'अपनी धरोहर, अपनी पहचान' 10
- एचडीएफसी बैंक उत्तर प्रदेश में लगाएगा 4 ऑक्सीजन संयंत्र 10

नोट :

- अनुपूरक बजट 11
- मुख्यमंत्री ने कई रियायतों की घोषणा की 11
- 'मिशन शक्ति' के तृतीय चरण का शुभारंभ 12
- राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण 12
- पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन 13
- लखनऊ में होगा ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन 13
- 'प्रयागराज कुंभ' 14
- 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' 14
- आयुष विश्वविद्यालय 15

दृष्टि The Vision

नोट :

दृष्टि
The Vision

नोट :

उत्तर प्रदेश

बाल सेवा योजना (Bal Seva Yojana)

चर्चा में क्यों ?

- 3 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों को बाल सेवा योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपए की मौद्रिक सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे, जिन्होंने कोविड-19 से अपने माता-पिता दोनों या किसी एक को खो दिया है; पात्र होंगे।
- इस योजना का लाभ प्रति परिवार से अधिकतम दो बच्चों को ही मिल सकता है।
- इस योजना का शत-प्रतिशत वित्तीयन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत उन मेधावी छात्रों को भी शामिल किया गया है, जो 23 वर्ष की आयु के हो चुके हैं और 12वीं के बाद राजकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से स्नातक, तकनीकी स्नातक या राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं।

झाँसी स्टेशन के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

- 03 अगस्त, 2021 को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानदं राय ने लोकसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झाँसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन' ('Veerangana Laxmi Bai Railway Station) करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है।

प्रमुख बिंदु

- किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिये संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है वहीं किसी गाँव या कस्बे या रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिये एक कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है।
- इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज तथा फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम 1857 की क्रांति की नायिका वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर करने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा गया है।
- उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित झाँसी उत्तर भारत में पुणे के पेशवाओं की एक महत्त्वपूर्ण रियासत और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्र रहा है।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया था।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय किसी भी रेलवे स्टेशन या स्थान के नाम को परिवर्तित करने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय, डाक विभाग तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति मिलने के उपरांत हरी झंडी देता है।

नोट :

UPEIDA-SIDM के बीच रक्षा उद्योग मंच के लिये समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

- 6 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority- UPEIDA) और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (Society of Indian Defence Manufacturers- SIDM) ने उत्तर प्रदेश में रक्षा उद्योग मंच (Defence Industry Forum) विकसित करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्ट-अप तथा रक्षा निर्माण इकाइयों को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश को रक्षा निर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करना है।
- इस समझौता ज्ञापन की वैधता तीन साल होगी और दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से रक्षा उद्योग मंच स्थापित किया जाएगा।
- UPEIDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार, समझौता ज्ञापन में रक्षा निर्माण में 1000 करोड़ रुपये के निवेश जुटाने की क्षमता है।
- इसी तरह UPEIDA ने रक्षा औद्योगिक गलियारे के झाँसी नोड पर कंपनी को 250 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने के लिये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किये हैं।
- उल्लेखनीय है कि SIDM रक्षा निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये एक गैर-लाभकारी संगठन समर्थन समूह है, जबकि UPEIDA उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल एजेंसी है।

उज्ज्वला योजना 2.0 (Ujjwala Yojana 2.0)

चर्चा में क्यों ?

- 10 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण 'उज्ज्वला योजना 2.0' की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 1 हज़ार महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन देकर उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत एक करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को न केवल मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिलेगा, बल्कि साथ में पहला रिफिल और हॉटप्लेट भी मुफ्त मिलेगा।
- इस योजना के पहले चरण में छूटे हुए और योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीब परिवारों को इस दूसरे चरण में लाभ मिलेगा।
- गौरतलब है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से की गई थी। उस समय पाँच करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था।
- अप्रैल 2018 में इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों और अति पिछड़ा वर्ग समेत सात श्रेणियों की महिलाओं को भी शामिल किया गया। साथ ही एलपीजी कनेक्शन के लक्ष्य को आठ करोड़ तक बढ़ाया गया, जिसे निर्धारित तिथि से सात महीने पहले अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया।

'काकोरी ट्रेन कांड'अब 'काकोरी ट्रेन एक्शन'

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के एक अहम् अध्याय 'काकोरी कांड' का नाम बदलकर 'काकोरी ट्रेन एक्शन' कर दिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इसका नाम इसलिये बदल दिया गया क्योंकि 'कांड' शब्द भारत के स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है।
- काकोरी ट्रेन एक्शन एक ट्रेन डकैती थी, जो 9 अगस्त, 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गाँव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी।
- इस डकैती कार्यवाही को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था।
- गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खान और रोशन सिंह को 19 दिसंबर, 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिये फाँसी पर लटका दिया गया था।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल' लॉन्च करते हुए 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान' की शुरुआत की, जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत राज्य में दो लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा देश के दो लाख राजस्व गाँवों में चार लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है।
- गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान 12 सदस्यीय समिति को मिलाकर 72,000 निगरानी समितियों का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्यों द्वारा घर-घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया।

परिवहन विभाग द्वारा संभावित लाभार्थियों के लिये पंजीकरण शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 11 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये उनका पंजीकरण शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इसमें जिन सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों, कंडक्टरों और सफाईकर्मियों की आजीविका लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई थी, उनका पंजीकरण शुरू किया गया है।
- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संदीप सैनी के अनुसार पात्र सार्वजनिक परिवहन परिचालक, परिचालक एवं सफाईकर्मी http://uk.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- इसके लिये आवेदकों को बैंक खाते के विवरण के अलावा, जिस वाहन पर वे काम करते हैं, उसके ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का उल्लेख करना होगा।
- सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बाद, आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में एक संदेश प्राप्त होगा। आवेदन को अस्वीकार करने का कारण संदेश में उल्लेखित किया जाएगा। आवेदक सही जानकारी के साथ फिर से आवेदन कर सकते हैं।
- विभाग द्वारा अगले छह महीनों के लिये लाभार्थियों को धन के आसान हस्तांतरण हेतु आवेदकों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके बैंक खातों और आवेदन में उल्लिखित नाम एकसमान है।

नोट :

हेमवती नंदन बहुगुणा (Hemvati Nandan Bahuguna)

चर्चा में क्यों ?

- 12 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के योजना भवन परिसर में चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव की श्रृंखला में पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही बहुगुणा के व्यक्तित्व और कार्यों पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन तथा 'हेमवती नंदन बहुगुणा' नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर बहुगुणा के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई।
- बहुगुणा जी का जन्म 25 अप्रैल, 1919 को वर्तमान उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के बुघाणी गाँव में हुआ था, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) में युवाओं को नेतृत्व प्रदान किया तथा बाद में नैनी के आसपास औद्योगिक विकास में मदद की।
- वर्ष 1952 में हेमवती नंदन बहुगुणा सर्वप्रथम विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। पुन: वर्ष 1957 से 1969 तक और 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे।
- बहुगुणा दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 8 नवंबर, 1973 से 4 मार्च, 1974 तक तथा दूसरी बार 5 मार्च, 1974 से 29 नवंबर, 1975 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों ?

- 13 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में गोरखपुर मंडल के 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- सम्मानित होने वालों में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अमरनाथ यादव, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज़ गजेंद्र राय, राष्ट्रीयस्तर की टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री शगुन कुमारी, राष्ट्रीयस्तर की हॉकी खिलाड़ी सुश्री मुस्कान पासवान, जिम्नास्ट विवेक यादव, वेटलिफ्टर विकास चौहान, राज्यस्तर के तैराक सौरभ शुक्ला, राष्ट्रीयस्तर की बास्केटबॉल खिलाड़ी सुश्री क्षमा गुप्ता तथा हैंडबाल खिलाड़ी सुश्री मुक्ता तिवारी प्रमुख रूप से शामिल हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने हेतु लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही।
- इस कार्यक्रम में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को डेढ़ करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए, हॉकी पुरुष टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को भी 1 करोड़ रुपए तथा महिला हॉकी टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- इस आयोजन में खेलों के कोच को भी सम्मानित किया जाएगा, साथ ही राज्य के सभी 75 ज़िलों से 75-75 खिलाड़ियों को विशेषतौर पर आमंत्रित किया जाएगा।

राष्ट्रपति वीरता पदक (President's Gallantry Medal)

चर्चा में क्यों ?

- 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के नौ पुलिसकर्मियों को वीरता के लिये राष्ट्रपति पदक, चार को विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पदक जबकि 73 पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिये पदक से सम्मानित किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जौनपुर के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी सहित नौ पुलिसकर्मियों को वीरता के लिये राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। इनमें अजय कुमार साहनी, बिजेंद्र पाल राणा, अक्षय शर्मा, भूपेंद्र कुमार शर्मा, सुनील नागर, तस्लीम खान, प्रवेश कुमार शुक्ला, पंकज मिश्रा और शैलेंद्र कुमार शामिल हैं।
- इसी प्रकार गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह, सीबी सीआईडी लखनऊ की एसपी गीता सिंह, ज़िला देवरिया के सब-इंस्पेक्टर वाजिद अली खान और 11 बीएन पीएसी, सीतापुर के प्लाटून कमांडर जगत नारायण मिश्रा को विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।
- वहीं, राज्य के 73 पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिये मेडल प्रदान किया गया।
- इस बीच, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, राज्य सरकार ने विभिन्न ज़ेलों से 75 महिला कैदियों को रिहा कर दिया।

'जन आशीर्वाद यात्रा'

चर्चा में क्यों ?

- 16 अगस्त, 2021 को मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश के सात नए मंत्रियों ने लोगों का आशीर्वाद लेने के लिये 'जन आशीर्वाद यात्रा' शुरू की।

प्रमुख बिंदु

- सोमवार से शुरू हुई यह यात्रा 20 अगस्त तक चलेगी और उत्तर प्रदेश के तीन दर्जन लोकसभा तथा 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुज़रते हुए 3,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी।
- लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से तीन अलग-अलग रथों पर सवार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लोगों का आशीर्वाद लेने पहुँचे।
- केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने मथुरा के वृंदावन से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और 19 अगस्त को बदायूँ में यात्रा समाप्त करेंगे।
- केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यात्रा की शुरुआत बस्ती से की।
- केंद्रीय आवास राज्य मंत्री कौशल किशोर मोहन ने उन्नाव से यात्रा निकाली और 18 अगस्त को सीतापुर में यात्रा का समापन करेंगे।
- उत्तर प्रदेश के इकलौते ब्राह्मण चेहरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने हरदोई के संडीला कस्बे में यात्रा निकाली और 19 अगस्त को अंबेडकर नगर में समाप्त करेंगे।
- केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा 17 अगस्त को ललितपुर से यात्रा शुरू करेंगे और 19 अगस्त को फतेहपुर में यात्रा समाप्त करेंगे।
- केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल 18 अगस्त को फिरोज़ाबाद से यात्रा शुरू करेंगे और मथुरा में समाप्त करेंगे।

एटीएस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र

चर्चा में क्यों ?

- 17 अगस्त, 2021 को राज्य सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देवबंद में नया एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके लिये सहारनपुर में देवबंद के पास 20,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुई आतंकी धमकियों के बाद लखनऊ में अलकायदा समर्थित संगठन के दो आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य सरकार ने आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।

नोट :

- प्रदेश भर से चुने गए करीब डेढ़ दर्जन तेजतर्रार एटीएस अधिकारियों को इस केंद्र में तैनात किया जाएगा।
- देवबंद के अलावा लखनऊ और नोएडा में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है।
- देवबंद से केवल 30 किमी. दूर सहारनपुर में हाल ही में आठ से अधिक आतंकवादियों और आईएसआई एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है।
- देवबंद में 300 से ज़यादा मदरसे हैं। दारुल उलूम के कारण ही देश-दुनिया से विद्यार्थी शिक्षा के लिये देवबंद आते हैं। ज्ञान की नगरी कहे जाने वाला देवबंद अब आतंकी गतिविधियों के चलते सरकार के रडार पर है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाने का फैसला किया है।

'अपनी धरोहर, अपनी पहचान'

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी 'अपनी धरोहर, अपनी पहचान' की भाँति प्रदेश के लिये तैयार की गई उत्तर प्रदेश एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी 'अपनी धरोहर, अपनी पहचान' को अनुमोदित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व निदेशालय (संस्कृति विभाग) द्वारा संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों का स्थलीय विकास, रखरखाव एवं जन-सुविधाओं का प्रबंधन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों व निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाएगा।
- इसके तहत संरक्षित स्मारकों/पुरास्थलों को विकसित करने के लिये निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाया जाना प्रस्तावित है।
- चयनित स्मारक मित्रों द्वारा स्वयं के संसाधनों से स्मारकों का स्थलीय विकास, पर्यटकों के लिये स्मारक परिसर में जन-सुविधा प्रबंधन एवं वार्षिक रखरखाव आदि की व्यवस्था की जाएगी।
- एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी के अंतर्गत चयनित स्मारक मित्र, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व निदेशालय (संस्कृति विभाग), पर्यटन विभाग एवं संबंधित ज़िले के ज़िलाधिकारी के मध्य एमओयू किया जाएगा, जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
- प्रस्तावित कार्य संस्कृति विभाग (उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व निदेशालय) एवं पर्यटन विभाग द्वारा संबंधित जनपद के ज़िलाधिकारी के माध्यम से पारस्परिक सहयोग से किया जाएगा।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्कृति विभाग एवं पर्यटन विभाग की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। संयुक्त समिति द्वारा निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार कार्य किया जाएगा।
- मंत्रिपरिषद द्वारा नीति के अंतर्गत प्रथम चरण में पुरातत्त्व निदेशालय (संस्कृति विभाग) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व विभाग के 11 प्रमुख स्मारकों/स्थलों का चयन स्मारक मित्र बनाए जाने के लिये किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।
- चयनित स्मारकों में छतरमंजिल एवं फरहत बख्श कोठी, कोठी गुलिस्ताने इरम, दर्शन विलास कोठी (कैसरबाग, लखनऊ), हुलासखेड़ा उत्खनन स्थल (मोहनलालगंज, लखनऊ), कुसुमवन सरोवर, गोवर्धन की छतरियाँ (गोवर्धन, मथुरा), रसखान समाधि (गोकुल, मथुरा), गुरुधाम मंदिर (वाराणसी), कर्दमेश्वर महादेव मंदिर (कंदवा, वाराणसी), चुनार किला (मिर्ज़ापुर) एवं प्राचीन दुर्ग (बरुआसागर, झाँसी) सम्मिलित हैं।

एचडीएफसी बैंक उत्तर प्रदेश में लगाएगा 4 ऑक्सीजन संयंत्र

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में एचडीएफसी बैंक के शाखा बैंकिंग प्रमुख अखिलेश कुमार रॉय ने बताया कि राज्य में परिवर्तन योजना के तहत बैंक द्वारा 4 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- अखिलेश कुमार रॉय ने राज्य में 'परिवर्तन' योजना के तहत ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना सहित बैंक की विभिन्न पहलों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिये एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्त्व करते हुए यह जानकारी दी।

नोट :

- बैंक अपने प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम 'परिवर्तन' के तहत उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये गोरखपुर, वाराणसी, भदोही और लखनऊ में चार ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा।
- ये ऑक्सीजन संयंत्र अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता वाले महत्त्वपूर्ण मामलों को संभालने में आत्मनिर्भर बनाएंगे और दूरस्थ स्थानों से ऑक्सीजन के परिवहन के लिये क्रायोजेनिक टैंकरों पर निर्भरता को समाप्त करेंगे।
- रॉय ने कहा कि इस महामारी में सरकार और कोविड वारियर्स की मदद के लिये बैंक ने यह पहल की है। बैंक इन चार शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिये 3 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

अनुपूरक बजट

चर्चा में क्यों ?

- 18 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिये अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस अनुपूरक बजट को पेश किया।
- यह अनुपूरक बजट चालू वित्त वर्ष के 5.5 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक बजट का केवल 1.33 प्रतिशत है। इस अनुपूरक बजट का फोकस रोज़गार के नए अवसर सृजित करने पर है।
- इस बजट में लोक कल्याण या किसी विशेष योजना को पूरा करने के अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें कुछ नई मांगें हैं, खासकर युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करने की, जिसके लिये 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिये सामाजिक सुरक्षा कोष, बिजली व्यवस्था में सुधार, अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, मवेशियों का संरक्षण तथा अयोध्या में बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कई रियायतों की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

- 19 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कई रियायतों की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने राज्य के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों के लिये महँगाई-भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं, प्रदेश रक्षा दल के जवानों, रोज़गार सेवकों के मानदेय में वृद्धि और वकीलों के लिये सुरक्षा निधि 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की।
- योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवाओं की सहायता के लिये 3,000 करोड़ रुपए की एक विशेष निधि (निधि) की स्थापना, डिप्लोमा और अन्य डिग्री धारकों को एक करोड़ स्मार्टफोन तथा टैबलेट के वितरण की भी घोषणा की।
- योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार योजना के लाभार्थी युवाओं को डिजिटल पहुँच प्रदान करने का खर्च भी उठाएगी।
- उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों को भी शामिल किया है, जो अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड से इस निधि और विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में योगदान देंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों का महँगाई-भत्ता 28 प्रतिशत (केंद्र के आदेश के अनुसार) बढ़ा दिया है। सरकार आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं/आँगनबाड़ी सहायिकाओं (AWWs/AWHs) के मानदेय में वृद्धि करेगी।
- मौजूदा डीए वृद्धि आदेश से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों एवं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

नोट :

'मिशन शक्ति' के तृतीय चरण का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 21 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में 'मिशन शक्ति' के तृतीय चरण का शुभारंभ हुआ। 'मिशन शक्ति' का यह चरण 31 दिसंबर, 2021 तक आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा वित्त मंत्री, भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण सम्मिलित हुईं।
- इस कार्यक्रम के दौरान 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना' के अंतर्गत पात्र लाभार्थी बालिकाओं के खाते में अनुदान की धनराशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया।
- इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति के प्रथम व द्वितीय चरण में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।
- इस अवसर पर 59 हज़ार ग्राम पंचायतों में 'मिशन शक्ति कक्ष' का शुभारंभ, बदायूँ में वीरांगना अवंतीबाई बटालियन के प्रांगण के शिलान्यास सहित विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए।
- ज्ञातव्य है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिये राज्य सरकार द्वारा 'मिशन शक्ति' संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण

चर्चा में क्यों ?

- 20 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी ने राजभवन के गांधी सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत में सर्वाधिक वादों के निस्तारण में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जनपद न्यायाधीशगण एवं सचिवगण, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि 10 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत में सर्वाधिक वादों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में इन जनपद न्यायाधीशगण व सचिवगण को सम्मानित किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से राज्य में 12 लाख से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया गया, जो देश में सर्वाधिक है।
- जनपद न्यायाधीशगण (सामान्य निस्तारण) के अंतर्गत ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश गोरखपुर दुर्ग नारायण सिंह, ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थनगर प्रमोद कुमार शर्मा तथा ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश रायबरेली अब्दुल शाहिद को सम्मानित किया गया।
- जनपद न्यायाधीशगण/पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतितोष अधिकरण के तहत जनपद आगरा के राजेंद्र प्रताप सिंह, जनपद अलीगढ़ के संजय सिंह तथा जनपद बरेली के मयंक चौहान को सम्मानित किया गया।
- जनपद न्यायाधीशगण/प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के राजकुमार बंसल, जनपद मेरठ के इरफान कमर तथा जनपद गाजियाबाद की श्रीमती अनीता राज को सम्मानित किया गया।
- सचिव, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (सी.डी.) के तहत अलीगढ़, बरेली, आगरा, गोरखपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, मेरठ, सिद्धार्थनगर तथा लखनऊ के सचिव क्रमशः महेंद्र कुमार, सत्येंद्र सिंह वर्मा, सुश्री मुक्ता त्यागी, देवेंद्र कुमार, सुमित कुमार, श्रीमती नेहा रूंगटा, श्रीमती अंजू कंबोज, चंद्रमणि तथा डॉ. सत्यवान सिंह को सम्मानित किया गया।
- सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति के तहत अशोक कुमार श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया।

नोट :

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन

चर्चा में क्यों ?

- 21 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

प्रमुख बिंदु

- सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हुआ। लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के सम्मान में उत्तर प्रदेश में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है तथा 23 अगस्त, 2021 के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।
- गौरतलब है कि कल्याण सिंह भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य 'उत्तर प्रदेश' के दो बार (जून 1991 से दिसंबर 1992 और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक) मुख्यमंत्री रहे।
- कल्याण सिंह ने 2014-2019 के बीच राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया।
- उनके पहले कार्यकाल को 26 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में लंबे समय से विवादित बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिये याद किया जाता है।

लखनऊ में होगा ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन

चर्चा में क्यों ?

- 24 अगस्त, 2021 को ब्रह्मोस एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक डॉ. सुधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि भारत का प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठान, 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (Defence Research and Development Organization-DRDO) निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे (Defense Industrial Corridor) के तहत लखनऊ में ब्रह्मोस की नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल का उत्पादन करेगा।

प्रमुख बिंदु

- यह बात डॉ. सुधीर कुमार मिश्रा ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान ब्रह्मोस परियोजना की वर्तमान गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए कही।
- DRDO की पहल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिये आवश्यक भूमि सहित अन्य सभी सुविधाएँ प्रदान करने का आश्वासन दिया।
- ज्ञातव्य है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को DRDO, भारत सरकार तथा NPOM, रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा परिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित किया जा रहा है।
- वर्तमान में भारतीय थल, जल एवं वायु सेना द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।
- ब्रह्मोस की नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल के उत्पादन के लिये लगभग 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी तथा इस परियोजना को पूर्ण करने के लिये लगभग 300 करोड़ रुपए की धनराशि निवेशित की जाएगी।
- इस परियोजना के माध्यम से लगभग 500 अभियंताओं एवं तकनीशियनों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 5,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होगा।
- इस मिसाइल के उत्पादन की योजना के लिये एन्सिलरी यूनिट्स भी स्थापित होंगी। इनके माध्यम से लगभग 10,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होने से उत्तर प्रदेश, देश का एयरोस्पेस और डिफेंस हब बनने की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा।
- इस परियोजना से डिफेंस कॉरिडोर को गति मिलेगी।
- ब्रह्मोस मिसाइल के विभिन्न सिस्टम तथा सब-सिस्टम के निर्माण से जुड़ी 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ भी परियोजना के निकट अपनी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने की ओर अग्रसर होंगी।

नोट :

'प्रयागराज कुंभ'

चर्चा में क्यों ?

- 25 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर प्रयागराज कुंभ, 2019 पर केंद्रित पुस्तक 'प्रयागराज कुंभ' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रयागराज कुंभ पर जनसाधारण को अर्पित इस पुस्तक के संपादक पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह हैं।
- इस पुस्तक का प्रकाशन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) द्वारा किया गया है।
- गौरतलब है कि प्रयागराज कुंभ, 2019 का आयोजन 15 जनवरी से 4 मार्च, 2019 तक किया गया था।
- प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इतनी बड़ी संख्या की निगरानी के लिये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया गया था। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी किया गया था।
- प्रदेश सरकार ने धार्मिक और आध्यात्मिक कलेवर के साथ कुंभ के दौरान वैश्विक स्तर पर स्वच्छता, सुरक्षा व सुव्यवस्था का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है।
- प्रयागराज कुंभ सामाजिक सद्भावना का भी प्रतीक बना है। प्रदेश सरकार ने कुंभ की विरासत को 'सर्व सिद्धिप्रद: कुंभ' के 'लोगो' के माध्यम से प्रचारित किया।
- गौरतलब है कि 450 वर्षों में पहली बार प्रयागराज कुंभ, 2019 में किला स्थित अक्षयवट एवं सरस्वती कूप को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिये खोला गया था।

'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना'

चर्चा में क्यों ?

- 25 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के द्वितीय चरण के अंतर्गत लाभार्थियों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन वितरित किया।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 10 अगस्त, 2021 को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के द्वितीय चरण का शुभारंभ प्रदेश के महोबा जनपद से किया गया है। इसके तहत देश में कुल 1 करोड़ निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन गरीब एवं ज़रूरतमंद परिवारों को प्रदान किये जाएंगे।
- 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के द्वितीय चरण हेतु प्रदेश के 10 जनपदों- सोनभद्र, बांदा, महोबा, चित्रकूट, रायबरेली, हरदोई, बदायूँ, अमेठी, फतेहपुर एवं फर्रुखाबाद का चयन किया गया है। इन जनपदों की 20 लाख लाभार्थियों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।
- गौरतलब है कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के प्रथम चरण के तहत देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। प्रदेश में योजना से 1.47 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। यह संख्या पूरे देश में सर्वाधिक है।
- 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के द्वितीय चरण में उन प्रवासी श्रमिकों के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं, जो 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के प्रथम चरण में पते के प्रमाण के अभाव में योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए थे।
- गौरतलब है कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत मार्च 2020 तक 8 करोड़ वंचित परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य था, जिसे 7 महीने पूर्व सितंबर, 2019 में प्राप्त कर लिया गया।

नोट :

आयुष विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

- 28 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- 21.173 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रहे इस विश्वविद्यालय की अनुमानित लागत 299.87 करोड़ रुपए है तथा इसके मार्च 2023 तक बन जाने की संभावना है।
- प्रदेश के आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी के सभी महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा।
- इस विश्वविद्यालय से राज्य में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी व सिद्धा चिकित्सा पद्धतियों का विकास होगा तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में छात्र-छात्राएँ दक्ष होंगे।
- विश्वविद्यालय का वास्तुशिल्प भारतीय संस्कृति के अनुरूप होगा। इसके परिसर में एकेडमिक भवन, प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन, छात्रावास, गेस्ट हाउस के अलावा ऑडिटोरियम और सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक भी होगा।
- गौरतलब है कि अब तक उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, सिद्धा की चिकित्सा पद्धति (जिन्हें समन्वित रूप में आयुष कहा जाता है) के लिये अलग-अलग संस्थाएँ रही हैं। प्रदेश में पहली बार आयुष पद्धतियों के पाठ्यक्रम का नियमन किया जा रहा है।
- प्रदेश में वर्तमान में आयुष महाविद्यालयों की कुल संख्या 94 है, जिसमें आयुर्वेद महाविद्यालय 67 (8 सरकारी व 59 निजी), यूनानी महाविद्यालय 15 (2 सरकारी व 13 निजी) तथा होम्योपैथी महाविद्यालय 12 (9 सरकारी व 3 निजी) हैं।

The Vision

नोट :